आईएस का खात्मा पर परिवारों का क्या?

बेन हबर्ड

© The New York Times 2019

आईएस के खात्मे के बाद सवाल यह है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्से से जो लोग इससे जुड़ने आए थे, उनके और उनके परिवारों का क्या होगा। सीरिया के अल होल युद्धबंदी शिविर में 72,000 लोग हैं, जिनमें विदेशी महिलाएं और बच्चे भी हैं। अनेक देशों ने यहां कैद अपने नागरिकों को वापस बुलाने से मना कर दिया है।

वह औरत इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के लिए नीदरलैंड्स से भागकर सीरिया आई थी। सीरिया आकर उसने आईएस के एक लड़ाके से शादी कर ली। वह योद्धा लड़ाई में मारा गया, तो उसने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद वह भी मारा गया। पर तब तक वह गर्भवती हो गई थी। इसी महीने आईएस के ध्वस्त हो जाने के बाद उसने अपने बेटे के साथ अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 'मैं अब सामान्य जीवन बिताने के लिए लौटना चाहती हूं', चौंतीस साल की जेनेटा कहती है।

एक सप्ताह पहले जब घोषणा हुई कि सीरिया में आईएस के ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, तो यह एक बड़ी घोषणा थी, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकी संगठन आईएस का नेटवर्क बेहद मजबूत था। पर आईएस के खात्मे के साथ एक सवाल यह खड़ा हुआ है कि दुनिया के अलग-अलग कोने से जो हजारों लोग इससे जुड़ने के लिए आए थे, अब उनका क्या होगा?

सीरिया के अल होल में, जो एक चट्टानी इलाका है, कतार से लगे तंबुओं में पिछले दिसंबर में आईएस के करीब 9,000 लड़ाके थे। इन तंबुओं में अब करीब 72,000 लोगों की भारी भीड़ है। ईंधन, भोजन और पानी के लिए बेहद लंबी कतारें लगती हैं। पिछले बृहस्पतिवार को विदेशियों के शिविरों में जाने पर हम पत्रकारों को अजीब दृश्य देखने को मिले। कीचड़ और गंदगी से भरे रास्ते के दोनों तरफ लगे सफेद तंबुओं में हमने महिलाओं के समूह को अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, डच और चाइनीज में बातें करते सुना। कीचड़ में सफेद और काले बालों वाले बच्चे खेल रहे थे। एक जर्मन महिला ने मुझे बताया कि वह अपने डॉक्टर पति के साथ यहां आई थी। पति की मौत के बाद अब वह समझ नहीं पा रही कि कहां जाए। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। 'मैं ऐसे समाज में अपने बच्चों को हरगिज नहीं पालना चाहूंगी, जो पूरी तरह भ्रष्ट हो और जहां अनैतिक काम को प्रोत्साहित किया जाता हो', नाम न बताने की शर्त पर उस महिला ने कहा। उनका कहना था कि सीरिया में रहना ही बेहतर है। इस समय जीवन भले ही थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके बाद परेशानी खत्म हो जाएगी।

हालांकि सीरिया से इराक तक फैले विराट भूभाग पर आईएस का कब्जा अब खत्म हो गया है, लेकिन शिविरों में रहने वाली महिलाएं अब भी आईएस के नियम-कायदे का पालन करती हैं। वे काला गाउन पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। बच्चों के कपड़े गंदे हैं और जूते कीचड़ में सने हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को खांसी है और उनकी नाक बह रही है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे नमकीन और सोडा बेच रहे हैं। जबकि बहुत सारे बच्चे भोजन, पीने के पानी और जेनरेटर के ईंधन के लिए कतारों में लगे हैं।

आईएस के युद्धबंदियों और उनके परिवारों के जो तीन शिविर हैं, पश्चिमोत्तर सीरिया में स्थित अल होल उनमें से सबसे बड़ा है। बाकी दो शिविर इराक और लीबिया में हैं। आंकड़े के मुताबिक, अल होल के शिविर में करीब 12,000 विदेशी महिलाएं और बच्चे हैं। यहां करीब 8,000 युद्धबंदी हैं, जिनमें से 1,000 विदेशी लड़ाके हैं। फ्रांस, रूस और चेचेन्या ने आईएस के लिए लड़ने आए कुछ लड़ाकों को अपने यहां बुला लिया है, लेकिन दूसरे देशों ने आईएस से जुड़े युवाओं को अपने यहां बुलाने से मना कर दिया है। इसीलिए विदेशी लड़ाके और औरतें यहां हैं।

स्थानीय कुर्दिश प्रशासन के पास इतने लोगों का इंतजाम करने की क्षमता नहीं है। उसकी आशंका यह है कि अगर अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला, तो आईएस फिर से उभर सकता है। कैंप के प्रशासकों में से एक मोहम्मद बशीर कहते है, 'हमें वैश्विक समर्थन और मदद बहुत ही कम मिल रही है।' इसी सप्ताह स्थानीय प्रशासन ने आईएस से जुड़े विदेशी लड़ाकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन की मांग की। लेकिन इस पर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं हुई।

जैसे ही मैं अपने फोटोग्राफर के साथ विदेशी युद्धबंदियों के शिविरों के अंदर गया, कुछ महिलाएं हमारी ओर आईं। वे जानना चाहती थीं कि हम उन्हें उनके देश वापस भेज सकते हैं या नहीं।

अल होल के इस शिविर में जितने लोग हैं, उसका दो तिहाई बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे अनाथ हैं। बहुत से बच्चों ने विस्तार से और बगैर किसी भावना या सहानुभूति के बताया कि उनके पिता किस तरह मारे गए। अनेक बच्चों ने अपनी आंखों के सामने हिंसा देखी है। प्रशासकों का कहना है कि आर्थिक मदद के अभाव में इन बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करना अभी तक उनके लिए संभव नहीं हो पाया है। इसके अलावा इन बच्चों के अभिभावक अब भी खलीफा की व्यवस्था में भरोसा करते हैं। दस साल के एक बच्चे से, जिसका एक पैर नहीं है, मैंने पूछा कि यह हादसा कैसे हुआ, तो उसका कहना था कि आसमान से हुए हमले में उसका एक पैर चला गया। मैंने उससे पूछा, 'अब तुम क्या करना चाहते हो?' उसका जवाब था, 'मैं तंबू या किसी घर में रहना चाहता हूं।' जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहां रहना चाहते हो, तो उसका बेहद संक्षिप्त उखड़ा हुआ जवाब था, 'मुझे पता नहीं।'

तेज विकास की ठोस बुनियाद

टीवी मोहनदास पई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार मई, 2019 में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इस दौरान उसने विकास और शासन के अनेक अनूठे मॉडल पेश किए जो कि महत्वपूर्ण ढंग से अतीत की सरकारों से अलग हैं। इन मॉडल का भारत के लोगों और इसकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। निश्चित रूप से यह वृहत अध्ययन की मांग करती है, ताकि भविष्य की सरकारों को राह मिल सके।

भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 2018 में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ 2.6 खरब डॉलर की हो गई और संकेत स्पष्ट हैं कि 2030 तक यह 10 खरब डॉलर की हो जाएगी! मोदी सरकार निश्चित ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुस्तरीय नीतियों और निवेश के साथ आगे बढ़ रही है।

उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि इस सरकार ने हाल की किसी भी सरकार की तुलना में भारत की सबसे बड़ी चुनौती-प्रत्येक भारतीय तक बुनियादी सुविधाएं-से निपटने के लिए अधिक काम किया है। सारे नागरिकों के लिए आवास, भोजन, पानी, बिजली और हर घर में शौचालय, हर घर में कुकिंग गैस, घर की पहुंच तक सड़क, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, सरकारी नकद हस्तांतरण के लिए बैंक खाता, वहन करने लायक डाटा प्लान सहित मोबाइल फोन, आयुष्मान भारत के तहत चिकित्सा बीमा, पहले से अधिक आर्थिक अवसरों के साथ नौकरियों की उपलब्धता और महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए गए हैं। 2022 तक ये सारे उपाय और अधिक तेज विकास के लिए ठोस बुनियाद उपलब्ध कराएंगे, और जिसमें जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, जैसा कि एक समाज के रूप में हमें अपने प्रत्येक नागरिक के लिए करना चाहिए।

आज सारे भारतीयों की सौ रुपये महीने पर असीमित डाटा तक पहुंच हो चुकी है। प्रति व्यक्ति प्रति माह 11 जीबी खपत के साथ भारत आज सेल्युलर डाटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

जियो ने उल्लेखनीय रूप से भारत में डाटा की पहुंच बढ़ाई है। आज सारे भारतीयों की सौ रुपये महीने पर असीमित डाटा तक पहुंच है। प्रति व्यक्ति प्रति माह 11 जीबी खपत के साथ भारत आज सेल्युलर डाटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना के साथ जन धन कार्यक्रम ने सभी तबके की उल्लेखनीय रूप से ऋण तक पहुंच सुनिश्चित की है। प्रत्येक नकद हस्तांतरण से सरकारी लाभ को फिर से परिभाषित किया गया है और लीकेज कम किया गया है। ये सारे शानदार उपाय हैं, जिनमें लाखों लाभार्थी लोगों की अर्थव्यवस्था में उत्पादक भागीदारी बढ़ाने की क्षमता है।

जीएसटी प्रणाली के जरिये कर सुधार ने भारत में पहली बार वस्तु और सेवा के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की रचना की है। महज पांच वर्ष के भीतर 29 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को एक प्रणाली के तले लाना वाकई उल्लेखनीय उपलब्धि है। शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है। आयात होने वाली प्रत्येक वस्तु पर जीएसटी लगाकर अनैतिक आयातकों द्वारा की जाने वाली कर चोरी को रोका गया है। पहली बार इमानदार करदाताओं को कर में छूट मिलने से लाभ मिला है। इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) ने दोस्ताना पूंजीपतियों को कर्ज लौटाने को मजबूर किया है और उनकी कई कंपनियों को जब्त किया है। इतिहास में हमने पहली बार देखा कि जिन लोगों ने हमारे बैंकों को लूटा उन्हें दिवालिया होना पड़ा और उनसे 45 फीसदी तक वसूली की गई। 'फोन' बैंकिंग अतीत की अवधारणा बन गई। बैंकों को अपने फंसे लोन की शिनाख्त करने को मजबूर किया गया और उनका पुनर्पूंजीकरण किया गया।

इन पांच वर्षों में देखा गया कि किस तरह से सड़क, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डों, जलमार्गों जैसी परियोजनाओं में लक्षित निवेश के जरिये तेजी लाई गई। सड़क परिवहन दिनोंदिन बेहतर होता जा रहा है, जिससे लागत कम होती जा रही है। रेलवे में अप्रत्याशित तरीके से किए निवेश के जरिये अब मानवरहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में साठ महीने के दौरान दोहरे अंक में वृद्धि देखी गई है।

भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार में जीडीपी में 76 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, वह भी महंगाई नियंत्रण और कम वित्तीय घाटे के साथ। शासन के मामले में इस सरकार का रिकॉर्ड उल्लेखनीय है। पिछले पांच साल में केंद्र सरकार में कोई घोटाला सामने नहीं आया। विपक्ष ने राफेल सौदे को लेकर सवाल उठाए, लेकिन वह कोई सुबूत पेश नहीं कर सका। सरकारी ठेकों में पूरी पारदर्शिता बरती गई।

ऐसे में भविष्य क्या है? भारत देश और भारतीय नागरिक आशावाद के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने भारत को बदल दिया है।

सर्वाधिक गरीबों के लिए 'न्याय'

प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की लागत 1,00,000 करोड़ रुपये है! कॉरपोरेट घरानों के दिवालिया होने से संबंधित मामलों में 84,000 करोड़ रुपये के कर्ज का निपटारा हो चुका है! तो फिर पांच करोड़ परिवार जीडीपी का छोटा-सा हिस्सा पाने के हकदार क्यों नहीं?

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

अंततः एक राजनीतिक दल ने एक कठोर फैसला करने का साहस दिखाया। लंबे समय से हम इस मुद्दे को नजरंदाज कर रहे थे, हम नैतिक तर्कों का सामना करने को तैयार नहीं थे और गरीबी को खत्म करने के लिए बुनियादी उपाय करने के प्रति अपनी अनिच्छा को छिपाने के लिए बहाने गढ़ते रहे।

भारत की एक बड़ी आबादी हमेशा से गरीब थी। (इसके लिए मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है)। स्वतंत्रता मिलने के समय हम अत्यंत गरीब थे। उस समय प्रति व्यक्ति आय (उस समय कीमत कम थी) 247 रुपये थी। कृषि क्षेत्र से बाहर बहुत कम लोगों के पास काम था। साक्षरता 17 फीसदी थी। औसत उम्र 32 वर्ष थी। ये सारे संकेतक भीषण और व्यापक गरीबी की ओर इशारा करते हैं।

इन 72 वर्षों में इन सारे संकेतकों में सुधार हुआ है। लाखों लोग कृषि क्षेत्र से बाहर आए हैं और संगठित क्षेत्र के रोजगार से जुड़े हैं। साक्षरता दर 73 फीसदी हो गई है, औसत उम्र 68 वर्ष हो गई है और वर्तमान मूल्य (2018) के आधार पर प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,12,835 रुपये है।

स्तब्ध करने वाली संख्या

हमें तो खुश होना चाहिए; लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात पर शर्मिंदा भी होना चाहिए कि तकरीबन 25 करोड़ लोग अब भी अत्यंत गरीब हैं। यदि हम ऐसे लोगों की गिनती करें जिनके पास ढंग का घर नहीं है (झोपड़ी नहीं); या जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है; या जिन्हें महीने में कई दिन पर्याप्त भोजन नहीं मिलता; या जिनकी आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है, तो यही संख्या सामने आएगी। हम तर्कसंगत तरीके से इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि लाखों लोग गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। सारे सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि 2004-05 से 2013-14 (यूपीए का कार्यकाल) के दौरान 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। एनडीए सरकार के कार्यकाल में संभवतः कुछ और लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले होंगे, लेकिन नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी के कारण कुछ लोग संभवतः गरीबी रेखा से नीचे भी गए होंगे। मेरा अनुमान है कि एनडीए सरकार में एक संख्या दूसरी संख्या को रद्द करती है। हमें इससे संबंधित आंकड़ों के लिए कुछ इंतजार करना होगा।

निष्कर्ष यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी गरीबी में गुजर-बसर कर रहा है। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक उनका हिस्सा 20 से 25 फीसदी तक है। आर्थिक प्रश्न है कि क्या हम उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए सिर्फ विकास पर भरोसा कर सकते हैं? नैतिक प्रश्न है कि क्या हमें उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए सिर्फ विकास पर भरोसा करना चाहिए?

आर्थिक दिमाग, नैतिक दिल

आर्थिक प्रश्न का उत्तर है कि हां, हम ऐसा कर सकते हैं। तेज विकास अंततः गरीबी को खत्म कर देगा। इससे हम एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने में भी सक्षम होंगे, जोकि किसी निजी हादसे या कारोबार में नाकामी के कारण किसी व्यक्ति के गरीबी रेखा के नीचे से चले जाने पर उसकी मदद करेगी। सार यह है कि इसमें वर्षों लग सकते हैं और तब तक अत्यंत गरीबों को बहुत मुश्किलों और अपमान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आर्थिक प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है।

जहां तक नैतिक प्रश्न के उत्तर की बात है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें विकास से परे जाकर चीजों को देखना होगा और भीषण गरीबी को खत्म करने के लिए अन्य तर्कसंगत उपाय करने होंगे।

एक उपाय जिसे अर्थशास्त्रियों और समाज विज्ञानियों के बीच व्यापक समर्थन मिला, वह है लक्षित आबादी को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण। वास्तव में 2014-2017 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में एक पूरा अध्याय इस विषय पर केंद्रित किया था।

सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूनिवर्सल बेसिक इन्कम- यूबीआई) पर अनेक वर्षों से बहस चल रही है। लक्षित समूहों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण यूबीआई का ही एक रूपांतरण है। इस विषय पर बहुत-सा साहित्य उपलब्ध है। इनमें प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण से संबंधित अनेक संदेहों के प्रभावी तरीके से उत्तर दिए गए हैं।

कांग्रेस पार्टी ने न्यूनतम आय योजना ('न्याय') की जो घोषणा की है, उसमें पांच करोड़ अत्यंत गरीब परिवारों के खाते में प्रति माह/वर्ष नकद हस्तांतरण किए जाने का वादा किया गया है। इसमें काफी धन लगेगा, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के 72 वर्ष बाद क्या भारत को गरीबी खत्म करने के लिए ऐसी योजना को अपनाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आर्थिक दिमाग और नैतिक दिल से दिया जाना चाहिए।

मेरे दृष्टिकोण में इसका एक ही उत्तर है : हां, हमें सारी चुनौतियों से निपटते हुए इसे करना चाहिए। एक अच्छी सरकार की गुणवत्ता किसी मुश्किल योजना के सफल अमल में निहित है, न कि नैतिक रूप से अनिवार्य और आर्थिक रूप से व्यावहारिक किसी योजना को ध्वस्त करने में।

संसाधनों पर पहला हक

भारत की जीडीपी, मौजूदा कीमतों पर, पिछले 15 वर्षों में बढ़ी है (तालिका देखें) और हर साल 11-12 प्रतिशत के बीच, मामूली रूप से बढ़ेगी:

2004-05: 32,42,209 करोड़ रुपये
2009-10: 64,77,827 करोड़ रुपये
2014-15: 1,24,67,959 करोड़ रुपये
2019-20: 2,10,07,439 करोड़ रुपये

2023-24 तक इसके 4,00,00,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है। वर्ष 2018-19 में केंद्र और राज्य सरकारों का कुल खर्च 60,00,000 करोड़ रुपये अनुमानित है और हर वर्ष राजस्व बढ़ने से यह आंकड़ा भी बढ़ेगा।

नैतिक-आर्थिक प्रश्न यह है कि क्या देश अत्यंत गरीब 20 फीसदी आबादी को गरीबी से उबारने में जीडीपी का दो प्रतिशत खर्च नहीं कर सकता। याद करें कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की लागत 1,00,000 करोड़ रुपये है! कॉरपोरेट घरानों के दिवालिया होने से संबंधित मामलों में अब तक 84,000 करोड़ रुपये के कर्ज का निपटारा हो चुका है! यदि चंद लोगों को ऐसा 'तोहफा' मिल सकता है, तो फिर पांच करोड़ परिवार (25 करोड़ लोग) जीडीपी या कुल खर्च का छोटा-सा हिस्सा पाने के हकदार क्यों नहीं हो सकते?

देश के संसाधनों पर गरीबों का पहला हक है। कांग्रेस ने इस सिद्धांत की पहचान की है और इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है।

कुंभ की गुप्त राजनीतिक उष्मा

संगम के तट पर बगल में डुबकी लगाने वाले की जाति और धर्म कोई नहीं पूछता। यहां आकर उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम का भेद मिट जाता है। भाषा कोई बाधा नहीं है। असली भारत इसी संस्कृति में बसता है।

भौतिक शास्त्र में गुप्त उष्मा के बारे में पढ़ाया जाता है। गुप्त उष्मा तापमान बदले बिना पदार्थ की अवस्था बदल देती है। सामाजिक-राजनीतिक जीवन में भी कई ऐसे मुद्दे, घटनाएं और आयोजन होते हैं, जो ऊपरी तौर पर तो सामान्य लगते हैं, लेकिन उनकी गुप्त उष्मा कई तरह के बदलाव लाने में सक्षम होती है। प्रयागराज में इस वर्ष मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक हुए कुंभ के आयोजन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

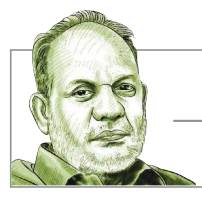

प्रदीप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

जिस आयोजन में चौबीस करोड़ लोग आएं और बिना किसी विघ्न-बाधा के अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था के अनुसार स्नान-ध्यान, पूजा, कल्पवास करके चले जाएं, वह सामान्य बात नहीं है। ज्यादातर कुंभ किसी न किसी विवाद के कारण याद किए जाते हैं।

पहले उन बातों का जिक्र कर लें, जो कुंभ में पहली बार हुईं। यूनेस्को ने इसे 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की सूची में सम्मिलित किया। चौबीस करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इकहत्तर देशों के राजदूतों ने इसकी तैयारी देखी और अपने राष्ट्रध्वज मेले में लगाए। प्रदेश सरकार के प्रयास और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से साढ़े चार सौ साल के बाद कुंभ में आए लोगों ने अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन किए। यह पहली ही बार हुआ कि कुंभ जैसे इतने वृहद स्तर पर हुए आयोजन में स्वच्छता के स्तर की चर्चा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हुई। इस आयोजन को सांस्कृतिक कुंभ, सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ की अवधारणा से जोड़ा गया। सड़क और रेल मार्ग के अलावा इसे वायुमार्ग (इतने बड़े पैमान पर पहली बार) और जलमार्ग से जोड़ा गया। प्रयागराज में चित्रकारी, स्वच्छता और शटल बसों के संचालन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया। यह भी पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों के पैर धोए। पचास दिन के इस पूरे आयोजन पर करीब चार हजार तीन सौ करोड़ रुपये खर्च हुए। सत्तर हजार करोड़ रुपये खर्च करके हुए राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से इसकी तुलना, शासन कौशल की कई बातें कहती हैं।

कुंभ के आयोजन से भारतीय जनता पार्टी और उसकी राज्य सरकार ने यह बता दिया कि जब वह हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तो उसका अभिप्राय क्या होता है। संगम के तट पर बगल में डुबकी लगाने वाले की जाति और धर्म कोई नहीं पूछता। यहां आकर उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम का भेद मिट जाता है। भाषा कोई बाधा नहीं है। यहां राजा प्रजा के पैर पखारता है। असली भारत अपनी इसी संस्कृति में बसता है। कुंभ का संबंध सागर मंथन से है, यह सबको पता है। यह भी कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ को वर्तमान स्वरूप दिया। मगर आज की परिस्थितियों में हर आयोजन को राजनीति के नजरिये से देखा जाता है। जबकि राजनीति के धर्म निरपेक्ष होने का मतलब है कि जीवन में जो भी श्रेष्ठ और नैतिक है, राजनीति का उससे कोई सरोकार नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के आयोजन को केवल हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं रखा, स्वच्छता के अभियान को भी मूर्त रूप में उतार कर दिखाया। उन्होंने दिखाया कि इतने बड़े आयोजन में सफाई के उच्चतम स्तर को बनाए रखा जा सकता है। यही कारण है कि कुंभ के बाद हर बार होने वाली बीमारी की इस बार कोई चर्चा तक नहीं है। कुंभ के कारण प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। सड़क, पुल, फ्लाईओवर के साथ ही प्रयाग में हवाई अड्डे का विस्तार और जलमार्ग शुरू होने की उपलब्धि को पूरे देश ने देखा।

सामाजिक-राजनीतिक जीवन में लोगों पर नेताओं की बातों का असर कितना और कितने समय तक रहता है, इस पर विवाद-बहस हो सकती है। लेकिन जमीनी स्तर पर हुए काम का असर देर तक रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। कुंभ में जो चौबीस करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने आए थे, वे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में क्या धारणा बनाकर गए होंगे, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए इस आयोजन का चुनाव पर असर न पड़े, यह कहना कठिन है।

इस बार के कुंभ के आयोजन में एक और बात पहली बार हुई। इस पूरे आयोजन में कहीं से भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के विरोधियों ने भी नहीं लगाया। कोई सरकार विभिन्न परियोजनाओं पर चार हजार करोड़ रुपये खर्च करे और भ्रष्टाचार की चर्चा तक न हो, यह आज के राजनीतिक माहौल में अजूबे से कम नहीं है। कुंभ के सफल आयोजन से योगी सरकार ने न केवल अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतिबद्धता दिखाई, बल्कि यह भी बताया कि धर्म, संस्कृति और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। कुंभ के इस आयोजन ने योगी सरकार के शासन कौशल की क्षमता का भी परिचय दिया है। ये सब बातें लोगों ने सरकार के प्रचार के बिना खुद अनुभव की हैं। इसलिए इसका असर काफी समय तक रहेगा। यही कुंभ की गुप्त राजनीतिक उष्मा है।